

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 643वीं बैठक दिनांक 05/05/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 8875/2021 Smt. Kalpana Sanvala, Owner, Village - Kasab, Tehsil - Susner, Dist. Agar Malwa, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.40 ha. (8,453 Cum per annum) (Khasra No. 2718), Village - Kasab, Tehsil - Susner, Dist. Agar Malwa (MP) Env. Consultant M/s. Amaltas Enviro Industrial Consultants LLP, Gurugram.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2718), Village - Kasab, Tehsil - Susner, Dist. Agar Malwa (MP) 1.40 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 540वीं दिनांक 08/01/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 05/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र सनवाला (अधिकृत प्रतिनिध) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स अमलतास इन्वायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरुग्राम (हरियाणा) उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लान में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र दो भागों में है । खदान अंदर उत्तर एवं दक्षिण दिशा में एच.टी लाईन के पिलर्स (खम्बे) लगे हुए दिखाई दे रहे हैं । परियोजन

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 मई 2023

प्रस्तावक ने इस संबंध में बताया कि समिति से टॉर प्राप्त करते समय एच.टी. लाईन/ खम्बे स्थापित नहीं थे इन खम्बों का प्रतिस्थापन अन्य क्षेत्र में प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र का पश्चिमी भाग एच.टी. लाईन होने के बजह से नॉन माईनिंग एरिया के रूप में छोड़ा जायेगा समिति ने विचार उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि इस संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी से स्पष्ट अभिमत लेकर आये कि एच.टी. लाईन/ खम्बे का प्रतिस्थापन अन्य क्षेत्र किया जायेगा एवं नॉन माईनिंग एरिया में चारागाह विकास का प्रस्ताव शामिल करते हुए ई.एम.पी. में प्रस्तुत करे ।

2. Case No 9849/2023 Shri Monhan Singh, Manager, Village Akyanjik, Tehsil Nagda, Distirct Ujjain (MP)- 456331, Prior Environment Clearance for Stone and M.Sand Quarry in an area of 1.50 ha. (Expansion from Stone-5250 to 8679 Cum per annum & M-Sand- 8001 Cum per annum, (Khasra No. 484, 487) Village-Akyanjik, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP)

This is case of M.Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 484, 487) Village-Akyanjik, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP) 1.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 05/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मोहन सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पांडा (ऑनलाईन) मे0. ओसियो इंवारेो मैनेजमेंट साल्यूशन इंडिया प्रा.लि. गाजियाबाद (उ.प्र) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5054 दिनांक 22/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 8.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है आवंटित खनन क्षेत्र के उत्तर दिशा में 34 मीटर एवं पूर्व में 370 दिशा में पक्का रोड है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये । साथ ही परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करले की पक्का रोड होने के कारण आवश्यक सेटबैक छोड़ने पर उत्खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध होगा या नहीं, ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये । अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये । समिति ने प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया कि प्रकरण क्षमता विस्तार Stone – 5250 m³/year to 8679 m³/year का है जबकि म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सीटीओ में Stone Sand – 2000 m³/year का उल्लेख है, इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक वास्तविक उत्पादन की स्थिति स्पष्ट करें । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है ।

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 मई 2023

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ने पत्र क्रमांक 369 दिनांक 17/03/21 के द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-50 के सरल क्रमांक-32 पर दर्ज है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

- 1- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण क्षमता विस्तार का है अतः पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रमाणित प्रति मय जिओटेग फोटोग्राफ्स के साथ ईआईए रिपोर्ट में प्रस्तुत करें ।
2. आवंटित खनन क्षेत्र के उत्तर दिशा में 34 मीटर एवं पूर्व में 370 दिशा में पक्का रोड है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये । साथ ही परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करले की पक्का रोड होने के कारण आवश्यक सेटबैक छोड़ने पर उत्खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध होगा या नहीं, ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
3. परियोजना प्रस्तावक ने क्षमता विस्तार का प्रकरण Stone – 5250 m³/year to 8679 m³/year जबकि म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सीटीओ अनुसार Stone Sand – 2000 m³/year का उल्लेख है, इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक वास्तविक उत्पादन की स्थिति स्पष्ट करें ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओवर बर्दन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

3. Case No 9852/2023 Shri Ramashankar Patel, Owner R/o Village Dhanwada, Tehsil Khirkiya, District Harda (MP)- 461331, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.776 ha. (40,020 Cum Per Year) (Khasra No. 115) Village-Dhanwada, Tehsil-Khirkiya, District-Harda (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 115) Village-Dhanwada, Tehsil-Khirkiya,

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2023

District-Harda (MP) 3.776 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 05/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रामशंकर पटेल (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार डॉ. धारणा तिवारी, मेसर्स अमलतास इवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसल्टेंट एलएलपी, गुरुग्राम। उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 17 दिनांक 06/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 11.729 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रश्नाधीन खदान का लैंड यूज शासकीय चारागाह के रूप में दर्ज है अतः इसी खसरे में चारागाह का विकास आवश्यक व्यय सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार पूर्व दिशा में 85 मीटर पर एवं उत्तर दिशा में 37 मी. पर पक्का रोड है तथा उत्तर पूर्व में 297 मी. पर आबादी है। अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-14 के सरल क्रमांक-1 पर दर्ज है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्व दिशा में 85 मीटर पर एवं उत्तर दिशा में 37 मी. पर पक्का रोड है तथा उत्तर पूर्व में 297 मी. पर आबादी है। अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान का लैंड यूज शासकीय चारागाह के रूप में दर्ज है अतः इसी खसरे में चारागाह का विकास आवश्यक व्यय सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. आवंटित खनन क्षेत्र पहाड़ पर स्थित है जिसमें कई पेड़ लगे हैं। अतः परियोजना प्रस्तावक खनन क्षेत्र में स्थित पेड़ों की इन्वेन्ट्री मय ड्रोन फोटोग्राफी/व्हीडियो ग्राफी ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 मई 2023

6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

4. Case No 9850/2023 M/s Jeet Asia Pvt.Ltd., Authorized Signatory Shri Sohan Lal Saini, R/o Chicholi, Tehsil Chicholi, District Betul (MP)- 460001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.415 ha. (99,997 Cum per annum) (Khasra No. 574/1) Village-Jhiraabannudhana, Tehsil-Chicholi, District-Betul (MP) (TP).

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 574/1) Village-Jhiraabannudhana, Tehsil-Chicholi, District-Betul (MP) 1.415 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 05/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सोहन लाल सेनी ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, मे0. ग्रीन सर्कल आई.एन.सी. बडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 616 दिनांक 04/04/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक यह खदान निजी भूमि पर अस्थाई अनुज्ञा के रूप में आवंटित है द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार उत्तर दिशा में 40 मी. पर दक्षिण दिशा में 69 मी. पर, पश्चिम दिशा में प्राकृतिक नाला है, दक्षिण दिशा में 60 मी0. की दूरी पर जल रोकने की संरचना स्थित है तथा उत्तर-पूर्व दिशा में एक पक्का रोड है। जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक बताया कि उत्तर दिशा में 40 मी प्राकृतिक नाला होने के कारण 10 मीटर का सेटबैक प्रस्तावित किया गया है। दक्षिण दिशा में जो वॉटरवाडी दिख रही है यह निजी उपयोग के लिए है जो कि 574/3 खसरे नंबर पर है उसके लिए भूस्वामी से अनापत्ती प्राप्त कर ली गई है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पश्चिम दिशा में खदान क्षेत्र का भाग नुकीलानुमा आकृति में अतः यह क्षेत्र नॉन माईनिंग के रूप में प्रस्तावित है प्रस्तुतीकरण में शामिल किया गया है। समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावित द्वारा जो खदान का एग्रीमेंट किया गया है वह 07 वर्षों का समझौता हुआ है जिसमें 10.00 लाख रुपये जमीन मालिक को दिया जाना प्रस्तावित है, परन्तु कब दिया जायेगा यह स्पष्ट नहीं है।

खदान क्षेत्र के अंदर कुछ पेड़ हैं। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन क्षेत्र में 15 पेड़ लगे हैं जिनमें से 10 काटा जाना प्रस्तावित है तथा उसके एवज में 100 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-41 के सरल क्रमांक-7 पर दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2023

योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन — 99,997 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 15.11 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.59 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम झिरनेबन्नुदाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 स्ट्रेचर एवं 5 व्हील चेयर्स एवं इसके अतिरिक्त पदस्थ चिकित्सक के परामर्श से आवश्यक सामग्री प्रदान की जाएगी ।	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव, फेसिंग तथा रख-रखाव के साथ प्रथम वर्ष में अनिवार्य रूप से किया जाये एवं 5 वर्ष तक की रखरखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को दी जाये) कम से कम 2500 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.	वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन (प्रथम वर्ष) ट्री गार्ड के साथ	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— सागौन, खमेर, पीपल, सिस्सू, बबूल, जंगल जलेबी, नीम, सीताफल, चिरोल आदि ।	650
2.	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर) (प्रथम वर्ष) ट्री गार्ड के साथ	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाखर, पीपल आदि ।	400
3.	गैर खनन क्षेत्र में कुल 50 पौधे रोपे जाएंगे। (प्रथम वर्ष)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— खमेर, पीपल, सिस्सू, बबूल, महुआ, जंगल जलेबी, अचार, नीम, सीताफल, चिरोल आदि ।	50
4.	ग्राम एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधों का वितरण (प्रथम वर्ष)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहल आदि ।	1400
योग			2500

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 मई 2023

5. Case No 9851/2023 Shri Shivam Paroha, Owner, Near Mahakaushal School, Rafi Ahmad Kidwai Ward, Murwara, District Katni (MP)- 483501, Prior Environment Clearance for Fire Clay Quarry in an area of 1.620 ha. (12,983 TPA) (Khasra No. 05, 06) Village-Bhaganwara, Tehsil-Bahoriband, District-Katni (MP) –TOR.

This is case of Fire Clay Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 05, 06) Village-Bhaganwara, Tehsil-Sleemanabad, District-Katni (MP) 1.620 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 05/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री शिवम परोहा और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1853 दिनांक 08/08/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिसका कुल क्षेत्रफल 04.99 हे० है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान दो भागों में विभक्त है। खदान का पश्चिमी भाग खुदा हुआ है एवं उसमें जलभराव है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में ये खदाने (05-06) मेसर्स ए.सी.सी. द्वारा संचालित थी परन्तु exhaust होने एवं अवधि समाप्त होने के कारण बंद है। समिति ने गूगल इमेज में पाया कि पूर्व दिशा में 250 मीटर के अंदर वन क्षेत्र परिलक्षित हो रहा है जबकि एकल प्रमाण-पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र 250 मीटर की परिधि पर कोई वन क्षेत्र स्थित नहीं है। समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि राजस्व विभाग से जानकारी प्रस्तुत करे कि उक्त क्षेत्र का लैंड यूज स्टेट्स में छोटे-बड़े झाड़ के जंगल के रूप में दर्ज तो नहीं है।

6. Case No 9848/2023 Shri Syed Jiya Rehman, Owner, R/o Village Ajayabanagar (Sund), Tehsil & District Raisen (MP)- 464551, Prior Environment Clearance for Flagstone Quarry in an area of 1.00 ha. (1503 Cum per annum) (Khasra No. 209) Village-Ajayabnagar (Sund), Tehsil-Raisen, District-Raisen (MP).

This is case of Flagstone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 209) Village-Ajayabnagar (Sund), Tehsil-Raisen, District-Raisen (MP) 1.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2023

आज दिनांक 05/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री एस.जे. रहमान ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स अमलतास इवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसल्टेंट एलएलपी, गुरुग्राम । उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1185 दिनांक 17/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, अतः जिसका कुल क्षेत्रफल 04.214 हे० है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है जिसके दक्षिण-पश्चिम दिशा में एक कच्ची रोड़ 10 मी० की दूरी पर स्थित है इसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि हॉलेज रोड़ के रूप में उपयोग में आती है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण फ्लेग स्टोन होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन ने पत्र क्रमांक 1282 दिनांक 18/11/2022 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर दिया जावेगा ।

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता फ्लेग स्टोन – 1503 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 02.33 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.56 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय प्राथमिक शाला सुंड में 2 बेंच व 05 कुर्सियों की व्यवस्था	10,000
ग्राम सुंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आवश्यकतानुसार सामग्री का वितरण	10,000
योग	20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 मई 2023

क्र.	वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन (प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष) ट्री गार्ड के साथ	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
2.	परिवहन मार्ग (पौधों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर) (प्रथम वर्ष) ट्री गार्ड के साथ	खमेर, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, बबूल, केतकी की स्लिप एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
3.	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, कतरी के बीज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
4.	ग्रामवासियो में वितरण हेतु ग्राम पंचायत सुंड))	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
5.	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत सुंड के चिन्हित क्षेत्र में (प्रथम वर्ष) ट्री गार्ड के साथ	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
6.	ग्राम पंचायत सुंड के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में (प्रथम वर्ष) ट्री गार्ड के साथ	कदम, नीम, खमेर, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
योग			1000

7. Case No 9853/2023 Shri Raghavendra Thakur, Owner, Ward No. 114, Shahpur Nagar Parisad District Sagar (MP)- 470001, Prior Environment Clearance for Stone and M-Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (Stone 7858 Cum Per Year & M-Sand 22004 Cum Per Year) (Khasra No. 37/1) Village-Maswasi Grant, Tehsil-Sagar, District-Sagar (MP)

This is case of Stone and M.Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 37/1 Part) Village-Maswasi Grant, Tehsil-Sagar, District-Sagar (MP) 2.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 मई 2023

आज दिनांक 05/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेंद्र ठाकुर ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 327 दिनांक 17/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, अतः जिसका कुल क्षेत्रफल 03.0 हे० है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान पहाड़ी पर स्थित है जिसमें कुछ पेड़ लगे हुये हैं। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन क्षेत्र में 05 पेड़ लगे हैं जिनमें से 01 काटा जाना प्रस्तावित है तथा उसके एवज में 10 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे। खदान के पूर्व दिशा में 318 मी. की दूरी पर पक्का रोड है एवं दक्षिण-पश्चिम दिशा में 184 मी. की दूरी पर कच्चा रोड है, दक्षिण दिशा में 370 मी० की दूरी पर एक एम.एस.डब्लू का शेड है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पौधारोपण के लिए खदान क्षेत्र के अंदर की स्वाइल प्रोफाईल का विवरण नहीं दर्शाया है अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित पौधारोपण स्कीम को अनुमोदित नहीं की जाती है अतः स्वाइल प्रोफाईल के साथ पौधारोपण स्कीम पुनः प्रस्तुत करे तत्पश्चात् इस प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

8. Case No 9854/2023 Shri Siddharth Kushwaha, Owner, Village Rusalla Bamora, District Sagar (MP)- 470004, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (19,629 Cum Per Year) (Khasra No. 37/1 Part) Village-Maswasi Grant, Tehsil-Sagar, District-Sagar (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 37/1 Part) Village-Maswasi Grant, Tehsil-Sagar, District-Sagar (MP) 2.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 05/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सिद्धार्थ कुशवाहा ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 326 दिनांक 17/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, अतः जिसका कुल क्षेत्रफल 04.00 हे० है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 मई 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान पहाड़ी पर स्थित है जिसमें कुछ पेड़ लगे हुये हैं। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन क्षेत्र में 05 पेड़ लगे हैं जिनमें से 01 काटा जाना प्रस्तावित है तथा उसके एवज में 10 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे। खदान क्षेत्र के पूर्व दिशा में एक पक्का रोड 119 मीटर की दूरी पर है। दक्षिण दिशा में 358 मी० की दूरी पर एक एम.एस.डब्लू का शेड है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पौधारोपण के लिए खदान क्षेत्र के अंदर की स्वाईल प्रोफाईल का विवरण नहीं दर्शाया है अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित पौधारोपण स्कीम को अनुमोदित नहीं की जाती है अतः स्वाईल प्रोफाईल के साथ पौधारोपण स्कीम पुनः प्रस्तुत करे तत्पश्चात् इस प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

9. Case No 9855/2023 Shri Jaswant Rathore, Owner, R/o Sadar Bazar Bangal No. 1, Sadar Bazar Cantt, Tehsil & District Sagar (MP) Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.70 ha. (24605 Cum Per Year) (Khasra No. 40) Village-Jasoda, Tehsil-Shahgarh, District-Sagar (MP)

This is case of Stone and M.Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 37/1 Part) Village-Maswasi Grant, Tehsil-Sagar, District-Sagar (MP) 2.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 05/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री एस.जे. रहमान ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 33 दिनांक 06/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, अत जिसका कुल क्षेत्रफल 03.40 हे० है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान पहाड़ी पर स्थित है जिसमें कुछ पेड़ लगे हुये हैं। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन क्षेत्र में 10 पेड़ लगे हैं जिनमें से 06 काटा जाना प्रस्तावित है तथा उसके एवज में 60 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे। खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा में 119 मीटर की दूरी पर एक नदी है, 273 मीटर की दूरी पर दक्षिण-पूर्व दिशा पक्का रोड है एवं 250 मीटर की दूरी पर कुछ मकान/शेड है। दक्षिण दिशा में 325 मी० की दूरी पर आबादी है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पौधारोपण के लिए खदान क्षेत्र के अंदर की स्वाईल प्रोफाईल का विवरण नहीं दर्शाया है अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित पौधारोपण स्कीम को अनुमोदित नहीं की जाती है अतः स्वाईल प्रोफाईल के साथ पौधारोपण स्कीम पुनः प्रस्तुत करे तत्पश्चात् इस प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

10. Case No 9075/2022 URMILA AGRAWAL, Owner, 82 Arvind Nagar, Aagar Road Ujjain, District Ujjain (MP) Prior Environment Clearance for Stone (Gitty) & M-sand Quarry in an area of 1.90 ha. (Stone Gitti-2105 m3/year and M Sand 40000 m3/year) (Khasra No. No. 821/1/2, 821/1/3, 821/3, 822), village Undasa Tehsil Ujjain District Ujjain (M.P.) Consultant Shri Amit Saxena Apex Mintech Udaypur (Rj.)

This is case of Stone (Gitty) & M-sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. No. 821/1/2, 821/1/3, 821/3, 822), village Undasa Tehsil Ujjain District Ujjain (M.P.) 1.90Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 561वीं दिनांक 21/03/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण समिति की 626वीं बैठक दिनांक 02/03/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री उर्मिला अग्रवाल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि आवंटित खदान के आक्षांश-देशांश अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आक्षांश-देशांश के अनुरूप नहीं है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा जो आक्षांश-देशांश प्रस्तुतीकरण में दिये गये हैं वे अनुमोदित खनन योजना के हैं अतः उन्हें मान्य किया जाये। समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के जो आक्षांश-देशांश प्रस्तुत किये गये हैं उनका प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा नहीं किया गया जो आवश्यक है क्योंकि वे सेक एवं सिया द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट से भिन्न हैं जिसमें समस्त अक्षांश-देशांश का प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा स्वयं किया गया है। अतः समिति की अनुशंसा है कि यह तथ्य सिया के संज्ञान में लाया जाये कि कई प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये आक्षांश-देशांश सेक एवं सिया द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुरूप नहीं उनमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये आक्षांश-देशांश का प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी से कराने के पश्चात् ही प्रकरण का परीक्षण किया जाना उचित होगा तथा इस प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक उनके द्वारा प्रस्तुत आक्षांश-देशांश का प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी से कराकर आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करे एवं यह प्रकरण नीति निर्धारण हेतु सिया की ओर अग्रेषित किया जाये।

सिया 778वीं बैठक दिनांक 29/03/23 को "ऐसे प्रकरण जिनमें जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश अनुमोदित माईनिंग प्लान से मिलान नहीं हो रहे हैं, उन प्रकरणों में संबंधित जिला खनिज अधिकारी से वास्तविक अक्षांश-देशांश अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत किये जाये साथ ही संबंधित जिला खनिज अधिकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं माईनिंग प्लान के अक्षांश-देशांश जिनसे संशोधन है उसे सक्षम प्राधिकारी से पुनः अनुमोदित कराकर सिया/सेक के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत किया जाये। उपरोक्त निर्णय के परिपालन में संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं कार्यपालन

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2023

संचालक, म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा खनन योजना के पूर्व जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं माईनिंग प्लान के अक्षांश-देशांश का मिलान किये जाने संबंधित जिलों एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किया जाये ।”

प्रकरण समिति के समक्ष आज दिनांक 04/04/23 को रखा गया, जिसमें जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री उर्मिला अग्रवाल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज के पत्र क्रमांक 629. दिनांक 10.03.2023 के द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित डी. एस.आर. कोऑर्डिनेट प्रस्तुत किये गये अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार

प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में 110 मीटर पर रेलवे लाईन, उत्तर-पश्चिम दिशा में 300 मीटर पर उन्दासा तालाब तथा खनन क्षेत्र से होकर एच.टी. लाईन गुजर रही है परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है इस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण में शपथ-पत्र में दर्शाया । एच.टी. लाईन के कारण 45 मीटर का सेटबैक दिया गया है, जो कि लगभग 0.0601 हे0 है, नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड़ने के पश्चात् एम-सेंड प्लॉट तथा स्टोन उत्खनन हेतु लगभग 01.2745 हे. उपलब्ध होता है जो कि आवेदित मात्रा के लिए पर्याप्त क्षेत्र है। आवंटित खनन क्षेत्र में 06 पेड़ लगे हैं जिनमें से 02 काटा जाना प्रस्तावित है तथा उसके एवज में 20 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे। इस खदान की जनसुनवाई के दौरान खेत में मिट्टी न जाये, खनन कार्य के कारण परेशानी है इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खनन कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है एवं एम-सेंड प्लॉट के चारों ओर विंड ब्रेकिंगवॉल बनायेंगे । वृक्षारोपण करने इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे इनको ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 2105 मी³ प्रति वर्ष एवं एम-सेंड – 40,000 मी³ प्रति वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 18.57 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.84 प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 02.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 मई 2023

सी.ई.आर. मदद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
चिकित्सा अधिकारी जिला उज्जैन से परामर्श करके ताजपुर गांव के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर आव यक चिकित्सक उपकरण उपलब्ध कराये जायेगे।	1,50,000
उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों, वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण तकनीक के लिए माधोपुरा एवं उण्डासा गांवों में शिविरों का आयोजन करना।	60,000
योग	2,10,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2320 वृक्षों का वृक्षारोपण :

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	संख्या
1.	बैरियर जोन (प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष) ट्री गार्ड के साथ	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, आम, जामुन, अमरूद, सिस्सू आदि।	475
2.	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर) (प्रथम वर्ष) ट्री गार्ड के साथ	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	600
3.	जहा खनन कार्य नहीं किया जायेगा (प्रथम वर्ष)	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि।	75
4.	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	1150
5.	पट्टा क्षेत्र के अंदर काटे जाने वाले वृक्षों के बदले लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	नीम	20
		योग	2320

11. Case No 9432/2022 Shri Shabbir Pakawala, Leasee R/o 16, Rambaag, District Ratlam (MP)-457001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (Expension from 3007 Cum per year to 20000 cum per year) (Khasra No. 273/17), Village - Rampuriya, Tehsil - Ratlam, Dist. Ratlam (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 273/17), Village - Rampuriya, Tehsil - Ratlam,

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2023

Dist. Ratlam (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 612वीं बैठक दिनांक 15/12/22 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री शब्बीर पकवाला (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री रीना त्रिवेदी एवं श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1845 दिनांक 10/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोडेड अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज को देखने पर समिति ने पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड खदान की आकृति का मिलान अनुमोदित खनन योजना (पेज क्रमांक-16) से नहीं हो रहा है। इसी प्रकार प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि **प्रकरण क्षमता विस्तार का है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण में वर्ष 2017 में डिया से पर्यावरणीय अभिस्वीकृति (प्रकरण क्रमांक-45/2017 दिनांक 22/08/17) प्राप्त की गई थी।** समिति ने पाया कि लगभग 05 वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार उनके द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण हेतु किए गए प्रयासों से समिति को अवगत नहीं करा सके और न ही ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत कर सके, जिससे यह ज्ञात हो सके कि विगत 05 वर्षों में उनके द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण हेतु कोई कदम उठाये गये हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोडेड अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज को देखने पर भी परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण हेतु किए गए प्रयासों के प्रमाण नहीं पाये गये। उपरोक्त परिदृश्य में समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक पूर्व की पर्यावरणीय अभिस्वीकृति में निर्दिष्ट शर्तों का पालन न कर क्षमता विस्तार हेतु प्रकरण प्रस्तुत कर रहे हैं, अतः समिति ने चर्चाकर निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक पहले अभी तक पर्यावरणीय संरक्षण हेतु किए गए प्रयासों की जानकारी (पूर्व पर्यावरणीय अभिस्वीकृति की शर्तों के अनुसार) मय फोटोग्राफ एवं दस्तावेजों के साथ एवं खदान की खसरा मेप एवं अनुमोदित खनन योजनानुसार आकृति एवं स्थिति की प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत करें, उसके पश्चात् टॉर हेतु विचार किया जाये एवं तब तक प्रकरण नस्तीबद्ध करने हेतु सिया को अग्रेषित किया जाये।

सिया की 765वीं बैठक दिनांक 10/01/22 को सेक की 612वीं बैठक दिनांक 15/12/23 की अनुशंसा उपरोक्त जानकारी शीघ्र प्रस्तुत की जाये जब तक प्रकरण को डिलिस्ट किया जाता है।

सिया की 775वीं बैठक दिनांक 17/03/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन एडीएस दिनांक 10/02/23 के माध्यम से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को रिलिस्ट कर सेक को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है।

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2023

प्रकरण को आज दिनांक 05/05/23 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री शब्बीर पकवाला (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री रीना त्रिवेदी एवं श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रमाणित प्रति मय जिओटेग फोटोग्राफ्स के साथ ईआईए रिपोर्ट में प्रस्तुत करें ।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
3. आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्वी भाग से लगा हुआ पुरानी संरचना या केशर स्थापित दिख रहा है यह क्या है इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट करे ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई अतः परियोजना प्रस्तावक जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे ।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

12. Case No 9667/2023 Shri Virendra Singh Gautam, R/o Ward No. 09, Maharana Pratap Nagar, Behind PG College, District-Sheopur (MP)-476337, Prior Environment Clearance for Bardha Bujarg Soil Quarry in an area of 1.00 ha. (2,000 Cum per annum) (Khasra No. 327/3), Village- Bardha Bujarg, Tehsil-Sheopur, District-Sheopur (MP)

This is case of Soil Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 327/3), Village- Bardha Bujarg, Tehsil-Sheopur,

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2023

District-Sheopur (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण समिति की 626वीं बैठक दिनांक 02/03/23 को प्रस्तुत हुआ था जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री वीरेन्द्र गौतम और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 10745 दिनांक 03/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि आवंटित खदान के आक्षांश-देशांश अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आक्षांश-देशांश के अनुरूप नहीं है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा जो आक्षांश-देशांश प्रस्तुतीकरण में दिये गये हैं वे अनुमोदित खनन योजना के हैं अतः उन्हें मान्य किया जाये। समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के जो आक्षांश-देशांश प्रस्तुत किये गये हैं उनका प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा नहीं किया गया जो आवश्यक है क्योंकि वे सेक एवं सिया द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट से भिन्न है जिसमें समस्त अक्षांश-देशांश का प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा स्वयं किया गया है। अतः समिति की अनुशंसा है कि यह तथ्य सिया के संज्ञान में लाया जाये कि कई प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये आक्षांश-देशांश सेक एवं सिया द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुरूप नहीं उनमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये आक्षांश-देशांश का प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी से कराने के पश्चात् ही प्रकरण का परीक्षण किया जाना उचित होगा तथा इस प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक उनके द्वारा प्रस्तुत आक्षांश-देशांश का प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी से कराकर आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करे एवं यह प्रकरण नीति निर्धारण हेतु सिया की ओर अग्रेषित किया जाये।

सिया 778वीं बैठक दिनांक 29/03/23 को "ऐसे प्रकरण जिनमें जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश अनुमोदित माईनिंग प्लान से मिलान नहीं हो रहे हैं, उन प्रकरणों में संबंधित जिला खनिज अधिकारी से वास्तविक अक्षांश-देशांश अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत किये जाये साथ ही संबंधित जिला खनिज अधिकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं माईनिंग प्लान के अक्षांश-देशांश जिनमें संशोधन है उसे सक्षम प्राधिकारी से पुनः अनुमोदित कराकर सिया/सेक के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत किया जाये। उपरोक्त निर्णय के परिपालन में संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं कार्यपालन संचालक, म.प्र. स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा खनन योजना के पूर्व जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं माईनिंग प्लान के अक्षांश-देशांश का मिलान किये जाने संबंधित जिलों एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किया जाये।"

प्रकरण समिति के समक्ष आज दिनांक 05/05/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री वीरेन्द्र गौतम और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए।

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज के पत्र क्रमांक 2335 दिनांक 21/03/23 के द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर दिशा में 10 मीटर की दूरी पर नहर जैसी संरचना दिख रही है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, श्योपुर संभाग श्योपुर के पत्र क्रमांक 305 दिनांक 21/9/22 का उद्धृत करते हुए बताया कि स्वीकृत क्षेत्र से लगभग 10 मीटर की दूरी पर नाली बरा निकला है जिसे किसानों द्वारा अपनी-अपनी निजी कृषिभूमि की सीमा में नाली बरा बनाकर आगे बढ़ाया गया है जो कृषि भूमि सिंचित करने के उपयोग में लिया जाता है, जो कि नहर नहीं है। स्वीकृत क्षेत्र से नहर की दूरी करीबन 1.5 किलोमीटर है। खदान के उत्तर दिशा में 20 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड़ है। किसानों द्वारा अपनी-अपनी निजी कृषिभूमि की सीमा में नाली बरा एवं कच्ची रोड़ के संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 50 मीटर का सेटबैक प्रस्तुतीकरण में दिया गया है एवं पूर्वी दिशा में 257 मीटर पर कच्चा रोड़ है तथा पश्चिम दिशा में 220 मीटर पर फार्म हाऊस है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मिट्टी – 2000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 05.10 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.37 प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मदद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम बर्धा बुजुर्ग शासकीय प्राथमिक शाला में 10 बेंच एवं डेस्क सेट प्रदान किये जावेंगे एवं साथ ही में 1 ब्लैकबोर्ड प्रदान उपलब्ध करवाया जावेगा।	30,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	संख्या
1.	बैरियर जोन (प्रथम वर्ष) ट्री गार्ड के साथ	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- इमारती लकड़ी वाले वृक्ष, बांस, सागौन, आम, जामुन, अमरुद, संतरा, कटहल, जंगल जलेबी, आवला, नीम, सीताफल आदि।	390
2.	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर) (प्रथम	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- करंज, आम, पाखर, पुत्रंजीवा नीम, सिस्सू, पीपल आदि।	65

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 मई 2023

	वर्ष) ट्री गार्ड के साथ		
3.	ग्रामीणों में पौधों का वितरण (प्रथम वर्ष)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- अमरुद, आम, जामुन, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहल, मुनगा आदि।	745
योग			1200

13. Case No 9668/2023 Shri Khum Singh Mandloi S/o Shri Harta Mandloi, Lessee, R/o Khamat, Tehsil-Sondwa, District-Alirajpur (MP)-457888, Prior Environment Clearance for Soliya Stone & M-Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone-3,000, M-Sand-74,600 Cum per annum) (Khasra No. 284), Village-Soliya, Tehsil-Sondwa, District-Alirajpur (MP)

This is case of Stone & M-Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 284), Village-Soliya, Tehsil-Sondwa, District-Alirajpur (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण समिति की 626वीं बैठक दिनांक 03/03/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री खुम सिंह मंडलोई (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, (गुजरात) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1372 दिनांक 22/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के अंदर एक क़शर स्थित है। खदान के दक्षिण-पूर्व किनारे से एक मौसमी नाला निकल रहा है। पश्चिम दिशा 186 मी. पर एक तालाब है, दक्षिण दिशा में 372 मी. एक स्टॉप डेम स्थित है एवं दक्षिण-पूर्व दिशा पर 258 मी. पर एक पक्का रोड है। मौसमी नाले के संरक्षण हेतु गारलैंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक भी प्रस्तावित किये गये हैं।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 1372 दिनांक 22/12/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा को डी.एस.आर. के चेप्टर-13 में प्रपोज़्ड एरिया सरल क्रमांक-7 पर इंड्राज किया गया है, जिसे आगामी सर्वेक्षण रिपोर्ट में मुख्य सूची में सम्मिलित किया जावेगा। चूँकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नहीं है अतः अनुमोदित खनन योजना में दिये गये अक्षांश-देशांश के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया। समिति ने चर्चा

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2023

उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि 624वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 26 फरवरी 2023 में लिये गये निर्णय अनुसार की अतः समिति का मत है कि इस स्थिति में उपरोक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्र०. 26 (स) के अनुसार सिया स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण सिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सिया 778वीं बैठक दिनांक 29/03/23 को “ऐसे प्रकरण जिनमें जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश अनुमोदित माईनिंग प्लान से मिलान नहीं हो रहे हैं, उन प्रकरणों में संबंधित जिला खनिज अधिकारी से वास्तविक अक्षांश-देशांश अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत किये जाये साथ ही संबंधित जिला खनिज अधिकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं माईनिंग प्लान के अक्षांश-देशांश जमसं संशोधन है उसे सक्षम प्राधिकारी से पुनः अनुमोदित कराकर सिया/सेक के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत किया जाये। उपरोक्त निर्णय के परिपालन में संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं कार्यपालन संचालक, म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा खनन योजना के पूर्व जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं माईनिंग प्लान के अक्षांश-देशांश का मिलान किये जाने संबंधित जिलों एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किया जाये।”

प्रकरण समिति के समक्ष आज दिनांक 05/05/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री खुम सिंह मंडलोई (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, (गुजरात) उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण पूर्व में डिया से ई.सी. पत्र क्रमांक 211 दिनांक 02/6/18 के माध्यम से प्राप्त की गई थी। समिति ने प्रस्तुतीकरण के दौरान डिया से प्रदाय की गई शर्तों का अवलोकन करने पर पाया कि परियोजना प्रस्तावक ने वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तों का पूर्णतः पालन नहीं किया है और न ही प्रस्तुतीकरण में वृक्षारोपण संबंधी डिया में प्रस्तुत ई.एम.पी., पौधारोपण योजना एवं सीईआर की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि डिया की शर्त के अनुसार कुल 4.0 हे. क्षेत्र में 45 पेड़ प्रति हे. की दर से करीब 200 पेड़ लगाये जाने थे जिसमें से हमारे द्वारा लीज क्षेत्र में 80 पौधे, स्कूल में 30 पौधे एवं 90 पौधे वितरण किया गया है। पौधारोपण कार्य दिनांक 01/5/23 को किया गया है। डिया की शर्त क्रमांक 06 सी.ई.आर. गतिविधि के अंतर्गत रु. 0.60 लाख का कार्य कराया गया है परियोजना प्रस्तावक ने उक्त कार्य ग्राम पंचायत से न कराकर स्वयं कराया है, जिससे यह स्पष्ट है कि पौधारोपण का कार्य समायावधि में नहीं किया गया तथा सोशलकार्य संबंधी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये जो डिया की शर्तों के अनुरूप नहीं है। खदान क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 168 मीटर की दूरी पर वॉटरवाडी होने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक ने 30 मीटर का सेटबैक प्रस्तावित किया है जिसे प्रस्तुतीकरण में शामिल किया है। तथापि अन्य शर्तों के पालन एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2023

प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 3000 मी³ प्रति वर्ष एवं एम-सैंड – 74,600 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.44 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.83 प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 02.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मदद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम सोलिया में हैंडपंप लगवाने का कार्य किया जावेगा उसके आस पास पानी कि निकासी के लिए कॉन्क्रीटिंग कि जावेगी ।	1 1,20,00
ग्राम सोलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ चिकित्सक के परामर्श से आवश्यक सामग्री प्रदान की जावेगी ।	80,000
योग	22,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4850 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	संख्या
1.	बैरियर जोन (प्रथम वर्ष) ट्री गार्ड के साथ	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पीपल, सिस्सू, बबूल, जंगल जलेबी, आवला, नीम, करंज, सीताफल, आम, चिरोल आदि ।	800
2.	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर) (प्रथम वर्ष) ट्री गार्ड के साथ	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, सिस्सू, पीपल, चिरोल, पुत्रंजीवा, करंज, कदम आदि ।	200
3.	ग्राम सोलिया के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में (प्रथम वर्ष)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कचनार, सिस्सो, चिरोल, नीम, बरगद, पीपल आदि ।	50
4.	ग्राम सोलिया एवं समीप स्थित ग्राम के	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आम, संतरा, मुंगा, जामुन, सीताफल, कटहल, संतरा आदि ।	3800

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 मई 2023

ग्रामीणों में पौधों का वितरण (प्रथम वर्ष)		
	योग	4850

14. Case No 9581/2023 Shri Aamin Hussain R/o Hussian Garden, Shankarpur, Transport Nagar, District-Gwalior (MP)-474010, Prior Environment Clearance for Chandeli Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (1,00,597 cum per annum) (Khasra No. 131/1 Govt. Land), Village-Chandeli, Tehsil-Vijaypur, District-Sheopur (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 131/1), Village-Chandeli, Tehsil-Vijaypur, District-Sheopur (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 625वीं बैठक दिनांक 01/03/23 को प्रस्तुत हुआ जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अमीन हुसैन (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा (ऑनलाईन) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 17575 दिनांक 06/09/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

यह अनुज्ञा शासकीय भूमि पर आवंटित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-24 के सरल क्रमांक-03 पर दर्ज है किंतु जो कोआर्डिनेट डी.एस.आर. में दिये हैं वह अनुमोदित खनन योजना में नहीं है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि डी.एस.आर. के कोआर्डिनेट अनुसार कुल रकबा 5.0 हे. आता है तथा माईन प्लॉन के कोआर्डिनेट अनुसार रकबा 4.0 हे. आता है चूंकि कोआर्डिनेट में अंतर है इस कारण यह विसंगति उत्पन्न हो रही है।

समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जो आक्षांश-देशांश अनुमोदित खनन योजना अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं उनका प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा से किया गया जो आवश्यक है क्योंकि वे सेक एवं सिया द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट से भिन्न है जिसमें उल्लेखित समस्त अक्षांश-देशांश का प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा स्वयं किया गया है। अतः समिति की अनुशंसा है कि यह तथ्य सिया के संज्ञान में लाया जाये कि कई प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये आक्षांश-देशांश सेक एवं सिया द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुरूप नहीं उनमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये आक्षांश-देशांश का प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी से कराने के पश्चात् ही प्रकरण का परीक्षण किया जाना उचित होगा तथा इस प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक उनके द्वारा प्रस्तुत आक्षांश-देशांश का प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी से कराकर आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करे एवं यह प्रकरण नीति निर्धारण हेतु सिया की ओर अग्रेषित किया जाये।

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 मई 2023

सिया 778वीं बैठक दिनांक 29/03/23 को “ऐसे प्रकरण जिनमें जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश अनुमोदित माईनिंग प्लान से मिलान नहीं हो रहे हैं, उन प्रकरणों में संबंधित जिला खनिज अधिकारी से वास्तविक अक्षांश-देशांश अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत किये जाये साथ ही संबंधित जिला खनिज अधिकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं माईनिंग प्लान के अक्षांश-देशांश जिनमें संशोधन है उसे सक्षम प्राधिकारी से पुनः अनुमोदित कराकर सिया/सेक के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत किया जाये ।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं कार्यपालन संचालक, म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा खनन योजना के पूर्व जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं माईनिंग प्लान के अक्षांश-देशांश का मिलान किये जाने संबंधित जिलों एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किया जाये ।”

प्रकरण समिति के समक्ष आज दिनांक 04/04/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अमीन हुसैन (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा (ऑनलाईन) उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज के पत्र क्रमांक 1787 दिनांक 01/03/23. के द्वारा प्रस्तुत अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर दिशा में 500 मीटर है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पौधारोपण के लिए खदान क्षेत्र के अंदर की स्वाईल प्रोफाईल का विवरण नहीं दर्शाया है

अतः समिति ने चर्चा कर यह निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत की जाये।

- स्वाईल प्रोफाईल के साथ पौधारोपण स्कीम पुनः प्रस्तुत करे ।
- ई.एम.पी. में चारागाह विकास का प्रस्ताव ।
- पुनरीक्षित सी.ई.आर योजना जिसमें पी.एच.सी. सेंटर में अद्योसंरचना विकास एवं उपकरण हेतु प्रस्ताव दे ।

15. Case No 8690/2021 Shri Rampratap Singh Bundela S/o Shri Sobran Singh Bundela, Jagatnagar, Tehsil - Mohangarh, Dist. Tikamgarh, MP - 472101 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (50000 cum per annum) (Khasra No. 40), Village - Magrai, Tehsil - Mohangarh , Dist. Tikamgarh (MP). Env. Consultant M/s. Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Noida, U.P.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 40), Village - Magrai, Tehsil - Mohangarh , Dist. Tikamgarh (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2023

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 518वीं दिनांक 08/10/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण समिति की 625वीं बैठक दिनांक 01/03/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री रामप्रताप सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि आवंटित खदान के आक्षांश-देशांश अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आक्षांश-देशांश के अनुरूप नहीं है तथा दोनों में अंतर लगभग 135 मीटर का आ रहा है जिससे आवंटित खनन क्षेत्र के लोकेशन बदल रही है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा जो आक्षांश-देशांश प्रस्तुतीकरण में दिये गये हैं वे डी.जी.पी.एस. करा के लिये गये हैं अतः उन्हें मान्य किया जाये। समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जो आक्षांश-देशांश डी.जी.पी.एस. करा के लिये गये हैं वे सिया द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट से भिन्न हैं जिसमें समस्त अक्षांश-देशांश का प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा स्वयं किया गया है। अतः समिति की अनुशंसा है कि यह तथ्य सिया के संज्ञान में लाया जाये कि कई प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये आक्षांश-देशांश सेक एवं सिया द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुरूप नहीं उनमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये आक्षांश-देशांश का प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी से कराने के पश्चात् ही प्रकरण का परीक्षण किया जाना उचित होगा तथा इस प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक उनके द्वारा प्रस्तुत आक्षांश-देशांश का प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी से कराकर आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करे एवं यह प्रकरण नीति निर्धारण हेतु सिया की ओर अग्रेषित किया जाये।

सिया 778वीं बैठक दिनांक 29/03/23 को "ऐसे प्रकरण जिनमें जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश अनुमोदित माईनिंग प्लान से मिलान नहीं हो रहे हैं, उन प्रकरणों में संबंधित जिला खनिज अधिकारी से वास्तविक अक्षांश-देशांश अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत किये जाये साथ ही संबंधित जिला खनिज अधिकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं माईनिंग प्लान के अक्षांश-देशांश जिनसे संशोधन है उसे सक्षम प्राधिकारी से पुनः अनुमोदित कराकर सिया/सेक के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत किया जाये। उपरोक्त निर्णय के परिपालन में संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं कार्यपालन संचालक, म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा खनन योजना के पूर्व जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं माईनिंग प्लान के अक्षांश-देशांश का मिलान किये जाने संबंधित जिलों एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किया जाये।"

प्रकरण समिति के समक्ष आज दिनांक 04/04/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री रामप्रताप सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज के पत्र क्रमांक 4556 दिनांक 07/03/23 में बिंदु क्रमांक-2 में उल्लेखित डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण के अक्षांश-देशांश को मान्य करते हुए प्रकरण का परीक्षण किये जाने

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 मई 2023

का अनुरोध किया है । उक्त डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण के आधार पर अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पूर्व दिशा में 65 मीटर की दूरी पर कच्ची सड़क एवं दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण दिशा में क्रमांश: 200 मीटर एवं 43 मीटर पर जल रोकने की संरचनाएं हैं । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पौधारोपण के लिए खदान क्षेत्र के अंदर की स्वाइल प्रोफाईल का विवरण नहीं दर्शाया है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उत्खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से करेंगे इस संदर्भ शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है । अतः समिति ने चर्चा कर यह निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत की जाये।

- स्वाइल प्रोफाईल के साथ पौधारोपण स्कीम पुनः प्रस्तुत करें ।

16. Case No 9409/2022 Shri Sana Ul Haq, Owner, Talab Road, Forest Dipo, Dist. Raisen, MP - 464551 Prior Environment Clearance for Flag Stone Quarry in an area of 1.314 ha. (2400 Cum per annum) (Khasra No. 209), Village - Sund, Tehsil - Raisen, Dist. Raisen (MP)

This is case of for Flag Stone. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 209), Village - Sund, Tehsil - Raisen, Dist. Raisen (MP) 1.214 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण पूर्व में सेक की 607वीं बैठक दिनांक 21/11/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

प्रकरण पूर्व में सेक की 611वीं बैठक दिनांक 21/11/22 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश मारु, अधिकृत प्रतिनिधि और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री जी.के. मिश्रा, मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंटरनेशनल, जयपुर उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा इस प्रकरण में पूर्व में पर्यावरणीय सलाहकार मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंटरनेशनल, जयपुर को अधिकृत किया गया था, जिनकी नेबिट एकीडिएशन सर्टिफिकेट की वैधता दिनांक 07/11/22 को समाप्त हो चुकी थी और मेरे प्रोजेक्ट में बिलंब न हो, इस दृष्टिकोण से मेरे द्वारा मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंटरनेशनल, जयपुर के स्थान पर मेसर्स अमलतास इन्वायरो इण्डस्ट्रीयल कंसल्टेंट, एलएलपी, गुरुग्राम हरियाणा से अनुबंध किया गया है, जो प्रस्तुतीकरण में दिया गया है । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 957 दिनांक 26/08/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 5.00 हे. से कम होने के कारण प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2023

आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा रायसेन जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके पेज नं. 23 के सरल क्रमांक-1 पर इस खदान का विवरण दर्ज है।

प्रकरण में प्रस्तुतीकरण के दौरान में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 957 दिनांक 26/08/2022 अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 74 की सीमा से 252 मीटर की दूरी पर है। समिति ने परिवेश पोर्टल पर इस खदान की स्थिति समझने हेतु जब वन क्षेत्र की लेयर अपलोड की तो आवेदित स्थल परिवेश पोर्टल अनुसार वनक्षेत्र की सीमा से 235 मीटर दूर आ रहा है। अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि उपरोक्त संदर्भ में संबंधित वन मण्डलाधिकारी से यह स्पष्ट प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये कि आवंटित खनन क्षेत्र वन क्षेत्र की अधिसूचित सीमा से बाहर है तथा उनको इस आवेदित स्थल पर खनन करने से विभाग कोई आपत्ति नहीं है।

इसी प्रकार आवंटित खनन क्षेत्र की दक्षिण दिशा से लगकर एक कच्चा रोड़ निकल रहा है तथा दक्षिण दिशा में 80 मीटर पर शेड भी है। समिति ने गूगल इमेज के अवलोकन से पाया कि आवंटित खनन क्षेत्र का अधिकांश भाग खुदा हुआ है जिसमें ब्लॉक माईनिंग कर Flag Stone का उत्पादन किया गया है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनको यह खदान पूर्व में वर्ष 2012 से 2022 तक आवंटित हुई थी जिसकी पर्यावरणीय स्वीकृति उनके द्वारा डिया से प्राप्त की गई थी। लीज अवधि समाप्त होने के कारण यह खदान उनको पुनः 22/04/22 को आवंटित हुई तथा खनन क्षेत्र में मौजूद पिट अनुमोदित खनन योजना में दिखाया गया है। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि गूगल इमेज के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरणीय अभिस्वीकृति (जो डिया से प्राप्त की गई है) की शर्तों के पालन हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया तथा परियोजना प्रस्तावक और उनके पर्यावरणीय सलाहकार भी इस संबंध में कोई प्रमाणिक जानकारी या छः-माही पालन प्रतिवेदन समिति के सक्षम प्रस्तुत कर सके चूंकि पूर्व में भी यह खदान इन्ही परियोजना प्रस्तावक को आवंटित थी अतः वे इस प्रकरण में डिया से प्राप्त ई.सी. की शर्तों का पालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ व छःमाही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अतः समिति ने निर्णय लिया कि इस प्रकरण में उपरोक्त कारणों से पर्यावरणीय अभिस्वीकृति की अनुशंसा किया जाना संभव नहीं है तथा प्रकरण सिया को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाये।

सिया की 764वीं बैठक दिनांक 14/12/22 को परियोजना प्रस्तावक डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये जाने तक प्रकरण को डिलिस्ट किया गया था।

सिया की 775वीं बैठक दिनांक 17/03/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 28/02/23 के माध्यम से डिया द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन मय फोटोग्रामफ के साथ प्रस्तुत कर जानकारी के आधार पर प्रकरण को रिलिस्ट करने का अनुरोध को मान्य करते हुए प्रकरण को रिलिस्ट कर सेक को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है।

प्रकरण को आज समिति के समक्ष आज दिनांक 05/05/23 को रखा गया, जिसमें जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सनाउलहक (ऑन लाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज.

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2023

मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंटरनेशनल, जयपुर उपस्थित हुए। प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक ने दिनांक 22/01/2023 के द्वारा सिया एवं सेक ई-मेल से डिया से प्राप्त ई.सी. की शर्तों का पालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ व छ:माही पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण में पूर्व में डिया से ई.सी. (दिनांक 10/06/16) जारी हुई थी समिति ने परीक्षण उपरांत पाया कि पुरानी स्वीकृत डिया प्रकरण फेंसिंग, वृक्षारोपण, सामाजिक कार्य नहीं किये गये परन्तु दिसंबर 2022 में फेंसिंग, गारलेंड ड्रेन का निर्माण कराया गया है जिसकी छाया चित्र प्रस्तुत की गई है। पैधारोपण योजना एवं सीईआर की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें पुरानी डिया की शर्तों के अनुरूप सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत गये खेल समग्री वितरण में रुपये 6000 व्यय किये एवं 300 पोधे लगा चुके हैं। दिनांक 04/07/22 को अनुमोदित माईन प्लॉन में कुल प्राप्त योग्य प्लेग स्टोन – 77,512 मी³ प्राप्त योग्य है जिसमें से 2400 मी³ माईनिंग अवधि में निकाला जावेगा। विशिष्ट शर्तों में उल्लेख है कि 06 मीटर से अधिक नहीं खोदेगे, माईनिंग खदान क्षेत्र के चारो ओर फेंसिंग कराई जायेगी। परियोजना प्रस्तावक ने उक्त कार्य ग्राम पंचायत से न कराकर स्वयं कराया है, जिससे यह स्पष्ट है कि पौधारोपण का कार्य समायावधि में नहीं किया गया तथा तथापि अन्य शर्तों के पालन एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता प्लेग स्टोन – 2400 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 05.14 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.55 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
शासकीय प्राथमिक शाला सुंड में 5 बेंच की व्यवस्था	5,000
ग्राम सुंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाहनुसार सामग्री का वितरण	15,000
योग	20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1214 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा(संख्या में)
1.	परिवहन मार्ग (पौधों की न्यूनतम ऊँचाई 01 (प्रथम वर्ष) ट्री गार्ड के साथ	खमेर, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी, कदम बबूल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 मई 2023

	मीटर)		
2.	गैर खनन क्षेत्र (प्रथम वर्ष)	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
3.	ग्रामवासियों में वितरण हेतु ग्राम पंचायत सुंड) (प्रथम वर्ष)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	550
4.	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत सुंड के चिन्हित क्षेत्र में (प्रथम वर्ष) ट्री गार्ड के साथ	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
6.	ग्राम पंचायत सुंड के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में (प्रथम वर्ष) ट्री गार्ड के साथ	कदम, नीम, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	114
कुल			1214

17. Case No 9670/2023 M/s. Universla Resources, Partner, Shri Subhash Chand Bansal, R/o MIG-II, Housing Board Colony, Near Shanti Nagar, District-Katni (MP)-483773, Prior Environment Clearance for Bhadawar Dolomite Mines in an area of 1.777 ha. (50,704 Tones per annum) (Khasra No. 640, 639, 649 Private Land), Village-Bhadawar, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP)

This is case of Dolomite Mines. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 640, 639, 649), Village-Bhadawar, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP) 1.777 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 624वीं बैठक दिनांक 26/02/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष चंद्र बंसल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मे0. ए सीरीज इंवारीटेक इंडिया प्रा. लि. नोएडा (उ.प्र) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 94 दिनांक 23/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रकरण प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि प्रकरण श्री के. दुर्गाराव के नाम से (Dolomite – 19000 TPA) लीज वर्तमान परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष चंद्र बंसल को स्थानांतरित हुई है और

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2023

वर्तमान उत्पादन क्षमता Dolomite – 50704 TPA बढ़ाकर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु केस फाईल किया गया है (पूर्व में इस प्रकरण में डिया के पत्र क्रमांक 235 दिनांक 01/10/18 के माध्यम से Dolomite – 19000 TPA हेतु ई.सी. श्री के. दुर्गाराव के नाम से प्राप्त है)। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा आवेदन नवीन प्रकरण के रूप में किया गया है।

समिति ने प्रकरण का अवलोकन किया एवं पाया कि प्राथमिक तौर पर प्रकरण क्षमता विस्तार का प्रतीत होता है, अतः समिति का मत है कि इस स्थिति में यह प्रकरण सिया की अनुशंसा एवं नीतिगत निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाये कि ऐसे प्रकरणों को नवीन प्रकरण मानकर परीक्षण किया जाये या क्षमता विस्तार का ताकि उसी आधार पर आवेदक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें, क्योंकि डिया से संबंधित ऐसे कई आवेदन / प्रकरण माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओए नं. 142/2022 में पारित आदेश दिनांक 07/12/2022 के अनुक्रम में सिया की 766वीं बैठक दिनांक 11/01/2023 में लिए गए नीतिगत निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होने की संभावना है।

सिया की 775वीं बैठक दिनांक 17/03/23 में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओए नं. 142/2022 में पारित आदेश दिनांक 07/12/2022 के अनुक्रम में सिया की 766वीं बैठक दिनांक 11/01/23 में लिए गए नीतिगत निर्णयानुसार डिया द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति में समस्त परियोजना प्रस्तावकों को परिवेश पोर्टल पर नवीन आवेदन किये जाने का लेख किया गया है। अतः उक्त प्रकरण को नवीन आवेदन के रूप में मान्य किया जाये एवं प्रकरण सेक को परीक्षण हेतु ऑनलाईन अग्रेषित किया गया है।

प्रकरण आज दिनांक 05/05/23 को समिति के समक्ष रखा गया जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष चंद्र बंसल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मे0. ए सीरीज इंवारेटेक इंडिया प्रा. लि. नोएडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार के अनुसार यह पुरानी खदान है जिसमें 3 से 4 मीटर के गड्ढे हैं इनकी वस्तुस्थिति स्पष्ट करे। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

- 1- पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रमाणित प्रति मय जिओटेग फोटोग्राफ्स के साथ ईआईए रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 मई 2023

- स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
 5. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।
 6. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. के साथ अनुमोदित डी.एस.आर. जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करे ।

18. Case No. - 5745/2018 M/s Virasha Infrastructure, Through Partner Shri Vivek Chauhan, 25-6, Walmi Road, Chunna Bhatti, Bhopal, (M.P.) – 462016. Prior Environment Clearance for Construction of Residential Project "Virasha Heights" on Khasra No. 401/4/1(kha), 401/4/2(kha), 401/2, 401/3, 401/4/4/4(gh), 401/4/3(ga), 401/4(ka), 401/4/3(kha), 400/2, 401/1 & 400/1), (Total Plot Area = 29914.72 sqm.) at Village - Banjari, Tehsil - Huzur & Dist. - Bhopal, (M.P.). Total Plot Area- 29914.72 m2 (2.99 Ha. Or 7.39 Acre) Total Built up Area – 44591.3 m2., Category: 8(a) Building & Construction Project. ENV Developmental Assistance Systems Pvt. Ltd, Lucknow (U.P.).

This is case of Proposed Residential Construction Project (Total Plot Area = 29914.72 sqm.) at Village - Banjari, Tehsil - Huzur & Dist. - Bhopal, (M.P.). Total Plot Area- 29914.72 m2 (2.99 Ha. Or 7.39 Acre) Total Built up Area – 44591.3 m2. Category: 8(a) Building & Construction Project. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

Earlier case was discussed in 331st SEAC meeting dated 25/10/2018, wherein PP and their consultant were present. During discussion and perusals of the documents it was observed by the committee that the it's a case of violation.

PP has proposed Rs. 222.0 Lakhs in EMP out of which the recurring cost is Rs. 26.1 Lakhs /Year has proposed. Rs. 31.00 Lakhs is proposed as remediation Cost for this project and PP, M/s. Virasha Infrastructure, Bhopal has proposed to submit bank guarantee of INR Rs. 31.00 Lakhs towards Remediation Plan. Committee after considering the reply recommends that PP may be asked to deposit the bank gurantee (BG) with three years validity of Rs. 31.00 Lakhs (equivalent to amount proposed in Remediation Plan /Restoration Plan) with

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2023

the MP Pollution control Board after approval of the SEIAA as per the procedure laid down in the MoEF&CC Notification dated 08/03/2018.

The EIA/EMP and other submissions made by the PP earlier were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of Environment Clearance for Construction of Residential Project "Virasha Heights" on Khasra No. 401/4/1(kha), 401/4/2(kha), 401/2, 401/3, 401/4/4/4(gh), 401/4/3(ga), 401/4(ka), 401/4/3(kha), 400/2, 401/1 & 400/1), (Total Plot Area = 29914.72 sqm.) at Village - Banjari, Tehsil - Huzur & Dist. - Bhopal, (M.P.). Total Plot Area- 29914.72 m² (2.99 Ha. OR 7.39 Acre) Total Built up Area – 44591.3 m²., Category: 8(a) Building & Construction Project, subject to the following special conditions and submission of bank guarantee (BG) with 03 years validity of Rs. 31.0 Lakhs (equivalent to amount proposed in remediation and resource augmentation plan).

Chronology of the project:

SN	Event Took Place	Date
1.	ToR for violation Recommended by SEAC	331 st SEAC meeting dated 25/10/2018.
2.	ToR for violation issued by SEAC	Letter No. No. 376 dated 07/12/2018.
3.	PP submitted EIA report	vide letter dated 03/08/2019, which was forwarded by the SEIAA vide letter no. 1900 dated 14/08/2019.
4.	Qry. in 394 th SEAC Meeting dated 31/08/2019.	PP Qry. Reply submitted vide letter dated 27/09/2019.
5.	EC recommended by SEAC	398 th SEAC meeting dated 04/10/2019.
6.	EC issued by SEIAA	EC issued vide letter no. 3702-03/SEIAA/2019 dated 04/01/2020.
7.	Bank Guarantee (BG) submitted by PP	BG No. 0579319BG0000205 dated 16/11/2019 . Amount Rs. 31.00 Lakhs
8.	Bank Guarantee Validity details	Valid up to 15/11/2022 Extended up to 15/11/2023 which was forwarded by the SEIAA vide letter no. 3315 dated 31/03/2023.
9.	PP request for release of BG	Letter dated 10/03/2023.
10.	SEIAA transfer of application for release of BG	Letter no. 3345/SEIAA/2023 dated 31/03/2023.

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2023

11.	GOI MOEF & CC Certified EC Compliance Certificate Report Status.	PP Submit Certified EC Compliance Certificate Report vide File No. 18-B-54/2020 (SEAC) dated 15/11/2022 (Copy attached).
12.	CA Certified Copy/ Bills/ Expenses Vouchers Copies.	

- Bank Guaranty Valid up to 15/11/2022 Extended up to 15/11/2023 which was forwarded by the SEIAA vide letter no. 3315 dated 31/03/2023.
- PP request for release of BG Letter dated 10/03/2023. SEIAA transfer of application for release of BG Letter no. 3345/SEIAA/2023 dated 31/03/2023.

The case was presented by the PP Shri Vipin Chauhan, wherein following details were presented by the PP:

परियोजना प्रस्तावक श्री विवेक चौहान, पार्टनर ने प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया कि उनके द्वारा रेमिडिएशन तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी रिसोर्स अगमेंटेशन प्लॉन से संबंधित कार्य पूरे किये जा चुके हैं तथा उनके द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी को वापिस करने के अनुरोध के साथ आवेदन प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि नियमानुसार भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा सर्टिफाईड कंप्लाइंस रिपोर्ट पत्र क्रमांक File No. 18-B-54/2020 (SEAC) dated 15/11/2022 के द्वारा जारी की गई है, जिसमें यह उल्लेख है, कि पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों का पालन उनके द्वारा किया जा रहा है।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री विवेक चौहान, उपस्थित हुए। श्री चौहान ने बताया कि उनके द्वारा रेमिडिएशन तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी रिसोर्स अगमेंटेशन प्लॉन से संबंधित कार्य पूरे किये जा चुके हैं सूचित किया गया है तथा पत्र दिनांक 10/03/23 के माध्यम से सिया कार्यालय में जमा कराया गया है जिसे सिया कार्यालय द्वारा पत्र क्र. 3345 दिनांक 31/03/2023 के माध्यम से इस कार्यालय में बैंक गारंटी की वैधता दिनांक 15/11/2023 बढ़ाते हुये प्रेषित किया है। विस्तृत प्रतिवेदन मय (रु. 31.00 लाख मात्र) प्रस्तुत किया जा चुका है। इसके साथ-साथ आपके द्वारा चाही गई जानकारी जैसे अभी तक विकसित ग्रीन बेल्ट की स्थिति मय फोटोग्राफ तथा ग्रीन बेल्ट को ले-आउट पर दर्शाते हुए भी प्रस्तुत कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में नियमानुसार भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा सर्टिफाईड कंप्लाइंस रिपोर्ट (पत्र क्रमांक 856 दिनांक 31/12/21) प्रस्तुत की गई है, जिसमें यह उल्लेख है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों का पालन उनके द्वारा किया जा रहा है अतः उनके बैंक गारंटी रिलीज करने का निवेदन है। समिति ने प्रकरण का अवलोकन किया एवं पाया कि परियोजना प्रस्तावक ने भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल से सर्टिफाईड कंप्लाइंस रिपोर्ट (पत्र क्रमांक EC Compliance Certificate Report vide File No. 18-B-54/2020 (SEAC) dated 15/11/2022) प्राप्त किये।

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 मई 2023

The Committee after discussion deliberated that to know different remediation measures taken by the Project Proponent against past damages took place (due to case of violation) hence, Committee recommended a site visit by a SEAC sub-committee wherein following members are nominated included namely-

1. Shri Dr. A. K. Sharma, Member
2. Shri Raghvendra Shrivastava, Member
3. Prof. (Dr.) Anil Prakash, Member

The sub-committee shall be carried - out a site visit within a week and submit a site visit report in the SEAC meeting for further consideration of the project.



(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव



(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2023

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2023

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2023

PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2023

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2023

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 05 मई 2023

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2023

30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- ‘D’

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2023

- an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
 29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
 33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2023

34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
- ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्टिपल जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

643वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2023

नोट 4 :- परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जायें ।

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास प्रजातियाँ ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियों, खस घास अगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीट
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बाँस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर